to give an answer straightway. But I could give the reasons, if what my hon. friend says is correct. Those ships may be engaged by the Indian shipping companies in those things which produce more foreign exchange for us than what we will save by carrying the PL 480 supplies.

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय ने कहा है कि अनाज लाने का आधा भाड़ा डालरों में दिया जायेगा। इस वक्त सारी दुनिया में चर्चा चल रही है कि हिन्दुस्तान में अकाल है और सब लोग अकाल ग्रस्त इलाकों की सहायता कर रहे हैं। इस अवस्था में क्या सरकार की ओर से अमरीका को कहा गया है कि इस साल यह डालर्ज़ की शर्त हटा दी जाये ?

Shri Sachindra Chaudhuri: As I said, it was very recently that the agreement was concluded in February this year, for the next year or the coming year, and in that, this question was raised, and in fact, I can give the information that the International Monetary Fund has sanctioned a loan of 187.50 million dollars to enable us to meet some of the freight charges.

श्री यशपाल सिंह : सरकार ने सौइंग सीज़न में पी० एल० 480 का तजुर्बा कर के देखा है। जब भारत की कोई भूमि इस को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है तो इस से भारत के नागरिक कैसे अपना स्वास्थ्य कायम रख सकते हैं ? जिस दिन से यह अनाज बाज़ार में आया है सिटिजन्ज़ बीमार होते जा रहे हैं और डाक्टरों की चांदी बनती जा रही है। क्या सरकार ने यह सोचा है कि सिटिजन्ज़ को मेडिकल एड दी जाये और डाक्टरों पर टैक्सेशन किया जाये ?

Shri Sachindra Chaudhuri: It is very difficult to answer the question, because I do not accept that when the PL 480 foodgrains started coming in here, because of something in them there has been an increase in the diseases. Having said that, how can I answer the next part of the question?

श्री यशपाल सिंह : भारतभूमि में इसको बो कर देखा जाय, इसका सोइंग एक्सपीयरेन्स किया जाय।

Shri H. N. Mukerjee: It is quite clear that 50 per cent of this freight has obligaterily to go in US vessels and it is also known that US shippers charge the highest rates in the world. We have no control over that 50 per cent. But in regard to the rest, may I know if any efforts have been made, in view of the recurring expenditure in shipping freight on foodgrain import for a long term of years already, to have a scheme of chartering vessels specially for the purpose of conducting the import of foodgrains that has become obligatory for us at the moment? Does the Finance Ministry in particular take any initiative in regard to having our own ships chartered, if necessry, by offering some more money which goes waste, if it goes into the pockets of the shippers of other countries?

Shri Sachindra Chaudhuri: If my friend says that it is well-known that the US freight charges are highest in the world, I am not in a position to contradict him. But I do say that we keep this matter under consideration all the time to find the best arrangement for freight. I do not agree with the hon. member that the PL 480 imports will go on for years to come and we have got to make any long-term arrangement. Therefore, no long-term arrangement is made. For short-term, certainly the necessary chartering is made.

Outlay of Plan Development

+

***746. Shri Madhu Limaye:**
Shri Kishen Pattnayak:

Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether in view of the suspension of foreign aid by Western Countries and the mounting defence

expenditure, the total outlay on Plan development is likely to be reduced; and

(b) the likely effects of the reduced development expenditure on agriculture, irrigation and fertilizer production?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). The outlay and size of Fourth Five Year Plan, as approved by the National Development Council in September, 1965, were given in the document "Fourth Five Year Plan—Resources, Outlays and Programmes". Copies of this document were furnished to the hon. Members. Certain adjustments, that are to be made to the detailed contents of the Plan, after taking into account subsequent developments, are under consideration.

श्री मधु लिमये : यह इतना लम्बा बयान है इसको ले क्यों नहीं लिया गया ?

श्री ल० ना० मिश्र : इसको अभी खत्म हूं ।

In view of the high priority attached to programmes of agricultural production, a reduction in the outlays on agriculture, irrigation and fertilizer production is not likely.

श्री मधु लिमये : अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि सरकार का जो शासकीय खर्च है, उसको कम कर विकास योजनाओं पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि विकास योजनाओं के अन्तर्गत भी शासकीय खर्चा होता है, जैसे इमारतों के ऊपर, एयाशी के ऊपर, फजूलखर्ची के ऊपर, बंगलों के ऊपर । क्या इस वक्त पैसे के अभाव को लेकर जो तकलीफ हम लोग उठा रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इस खर्चे को भी घटाया जायगा ।

श्री क० ना० तिवारी : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, ऐयाशी शब्द ठीक नहीं है . . .

श्री मधु लिमये : ऐयाशी में क्या खराब है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐयाशी लफ्ज ठीक नहीं है, जैसा श्री यशपाल सिंह जी कहा करते हैं, वह लफ्ज नाचने-गाने या कल्चरल प्रोग्राम में इस्तेमाल होता है ।

श्री मधु लिमये : मिसाल के तौर पर कई सिंचाई योजनाओं में कई डाक-बंगले बने हैं, पांच-पांच लाख रुपये खर्च कर के ।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐयाशी कैसे हुई ?

श्री मधु लिमये : हम जो गरीब देश हैं, . . .

एक माननीय सदस्य : इसको फ़जूलखर्ची कह सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह एयाशी नहीं है, फ़जूलखर्ची कह सकते हैं । ऐयाशी के मायने बुरे होते हैं ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, . . .

अध्यक्ष महोदय : ऐयाशी लफ्ज से उनका जो मतलब है, वह लक्जरी से है ।

श्री शिव नारायण : सोसायटी जिस लफ्ज को बुरा माने उसको वह पार्लियामेन्ट में कैसे कह सकते हैं ?

Shri Kapur Singh: "Aiyashi" simply means aristocratic living. That is the literary, dictionary meaning of the word.

Mr. Speaker: Aristrocratic living also includes certain things that are not liked.

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग प्राजेक्ट्स पर खर्च करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे को घटाना चाहते हैं । बिहार में डाक बंगले का जो माननीय सदस्य ने उल्लेख किया तो क्या उनको ख्याल है कि योजना को पूरा करने के लिये पहले 4–5 साल से वे इन्जीनियर्स वहां

पर किस तरह से रहते थे, जंगलों में, पहाड़ों पर, धूप में, पानी में वहां पर रहते हुए योजना को पूरा करते थे, अगर उनके लिये एक-आध डाक-बंगला बना दिया गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वे लक्ज़री से रहते हैं ।

श्री मधु लिमये : इन्होंने पूरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया । मैंने यह सवाल पूछा था कि विकास योजनाओं के अन्तर्गत भी जो शासकीय खर्चा होता है, जैसे अभी रांची में हैवी इन्जीनियरिंग के कारखाने की इतनी आलीशान इमारत बनाई गई है, जब कि पूर्वी जर्मनी में मैं वार्नीमुंडे के एक जहाज के कारखाने को देखने गया, उसकी मामूली इमारत थी । वह लोग पैदावार पर जोर देते हैं, जहाजों का उत्पादन बढ़े, यह नहीं की आलीशान इमारतें खड़ी करें । मेरे प्रश्न का जवाब आना चाहिये ।

श्री ल० ना० मिश्र : यह प्रश्न नहीं है, एक सुझाव है, इसको देखा जायगा ।

श्री मधु लिमये : इस वक्त कृषि, सिंचाई और उर्वरक (फ़र्टीलाइज़र) इनकी आवश्यकता को देखते हुए, क्या सरकार अन्य महकमों पर जो खर्चा होता है, उसको और घटाकर, इन कामों पर और ज्यादा पैसा लगायेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सही है कि जितना हो सके खर्चा घटाया जाय । कोई अनलिमिटेड इक्सपेन्डिचर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर नहीं होता हैं, ऐसा होता है कि इस पर खर्चा 7 वा 10 परसेन्ट रहे, इस तरह के खर्च पर उससे ज्यादा खर्च नहीं हो सकता है । लेकिन जहां तक सुझाव का सम्बन्ध हैं, खर्चा जितना घटे उतना अच्छा हैं ।

Shrimati Savitri Nigam: In view of the fact that education of the handicapped children, who are in a very large number, about two crores, in our country, has been neglected so far, may I know whether a substantial amount has been allotted for this purpose in the Fourth Plan outlay or not?

Shri L. N. Mishra: I will draw the attention of the hon. Member to the social welfare side of the programme as mentioned in the booklet. She will kindly refer to that and find out the information. The detailed programme she will know later.

श्री रामेश्वरानन्द : अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि वहां बिहार में इन्जीनियर्स धूप में बैठे रहे, सर्दी में बैठे रहे, वर्षा में बैठे रहे, इसलिये कहीं कहीं ऐसे भवन बना दिये गये हैं, . मैं पूछना चाहता हूं कि इसी सदन के बिलकुल निकट ट्रांस्पोर्ट भवन बना हुआ है—सात मन्ज़िला, यहां पर लोग कौन सी तपस्या करते रहे हैं जो आप ने बना कर खड़ा कर दिया है ।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : यह चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं । हम इसलिये सात-सात मन्ज़िले मकान बना रहे हैं कि आसमान की तरफ़ जायं, जो महंगी ज़मीनें हैं, उसका अच्छा इस्तेमाल करें ।

श्री रामेश्वरानन्द : इस तरह से आप पैसा बहा रहे हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या प्रधान मंत्री विदेश जा र इसलिये विदेश मंत्री भी उनसे चार्ज ले रहे हैं ।

दिल्ली में आय-कर कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल

*747. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों ने दिसम्बर, 1965 में दिल्ली कार्यालय के सामने भूख हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?